(घ) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा पुलिस तथा बिहार सरकार के अन्य अधिकारियों को आवंटित की गई विभिन्न प्रकार के आवासीय इकाइयों/क्वार्टरों की संख्या तथा इन आवासीय इकाइयों/क्वार्टरों के रख-रखाव पर संयंत्र प्रबन्धन द्वारा प्रतिमाह खर्च की जा रही राशि निम्नानुसार है:—

क्र०सं०	अधिकारीगण/विभागों की श्रेणी	क्वार्टरों की संख्या टाइप-वार						मासिक रख-रखाव लागत		
		क	ख	ग	घ	ङ	होस्टल	एल० एच०	कुल	(रुपये)
1.	पुलिस (पुलिस उप महानिरीक्षक/कोल फील्ड्स, पुलिस अधीक्षक/बोकारो होम गार्ड्स बी०एम०पी० IV	2	10	33	88	108	—	9	250	52,083
2.	राज्य सरकार के अधिकारीगण (पुलिस को छोड़कर)	1	28	72	48	142	14	20	325	67,709
	कुल:	3	38	105	136	250	14	29	575	1,19,792

चूना पत्थर का उत्पादन

2946. **श्री गया सिंह:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीन नन्दनी खानों में पिछले एक वर्ष से चूना-पत्थर का उत्पादन घटाने के क्या कारण हैं और मशीनों के रख-रखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रति माह चालीस हजार टन चूना-पत्थर निजी क्षेत्र से अधिक मूल्य पर खरीद रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) यह सच नहीं है कि पिछले एक वर्ष से भिलाई इस्पात संयंत्र की नदनी खान में चूना-पत्थर का उत्पादन कम हो रहा है। वर्ष 1991-92 में उत्पादन 11,16,500 टन हुआ जबकि 1990-91 में 8,56,400 टन उत्पादन हुआ था। नन्दिनी में उपकरणों के अनुरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) और (ग) कन्वर्टर प्रक्रिया के माध्यम से इस्पात उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में निम्न सिलिका युक्त चूना-पत्थर की आवश्यकता होती है। नन्दिनी खान से उपलब्ध होने वाला चूना पत्थर बहुत उच्च सिलिका युक्त होता है इसलिए यह कन्वर्टरशाला के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तदनुसार बाह्य स्रोतों से निम्न सिलिका युक्त चूना पत्थर की खरीद करनी पड़ती है। वर्ष 1991-92 में कन्वर्टर प्रक्रिया के माध्यम से केवल इस्पात निर्माण में इस्तेमाल के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लगभग 3 लाख टन निम्न सिलिका युक्त चूना पत्थर की खरीद की गयी थी जो औसतन लगभग 25,000 टन प्रतिमाह है।

Steel Production in the Company

2947. SHRI P. UPENDRA : Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether steel production in the country has been stagnating at around 13 to 14 million tonnes, necessitating imports;

(b) whether Government have decided to support the initiative of the private sector in steel making; and